



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 320]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 17, 2017/श्रावण 26, 1939

No. 320]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 17, 2017/SRAVANA 26, 1939

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 27 जुलाई 2017

सं. टीएमपी/25/2016-केपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार, कांडला पत्तन न्यास (केपीटी) से केपीटी के गांधीधाम टाउनशिप के दर ढांचे के संशोधन के लिए प्राप्त प्रस्ताव का निपटान करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

सं. टीएमपी/25/2016-केपीटी

कांडला पत्तन न्यास (केपीटी)

आवेदक

कोरम

(i). श्री टी.एस. बालासुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)
(ii). श्री रजत सचर, सदस्य (अर्थशास्त्र)

आदेश

(जुलाई, 2017 के 21 वें दिन पारित)

यह मामला कांडला पत्तन न्यास (केपीटी) से केपीटी के गांधीधाम टाउनशिप के दर ढांचे के संशोधन के लिए प्राप्त प्रस्ताव दिनांक 11 अप्रैल 2016 से संबंधित है।

2.1. इस प्राधिकरण ने आदेश सं. टीएमपी/20/2010-केपीटी दिनांक 9 अप्रैल 2012 द्वारा केपीटी गांधीधाम टाउनशिप के लिए पट्टा किराया अनुमोदित किया था। यह आदेश अधिसूचना सं. 119 दिनांक 4 मई 2012 द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। इस प्राधिकरण द्वारा संशोधित पट्टा किराये 01 जनवरी 2009 से पूर्वव्यापी प्रभाव से कार्यान्वित किए गए थे और पांच वर्षों की अवधि अर्थात् 31 दिसम्बर 2013 तक वैध थे।

2.2. उसके बाद, इस प्राधिकरण ने, केपीटी द्वारा किए गए अनुरोध के आधार पर, अपने आदेशों दिनांक 30 जून 2014, 31 दिसम्बर 2014 और 30 जून 2015 द्वारा केपीटी की गांधीधाम टाउनशिप भूमि के लिए मौजूदा दर ढांचे की वैधता को समय-समय पर विस्तारित किया था। प्रत्येक विस्तार के समय, इस प्राधिकरण ने पत्तन को सलाह दी थी कि गांधीधाम टाउनशिप भूमि के लिए दर ढांचे के संशोधन के लिए अपना प्रस्ताव दाखिल करे। तथापि, पत्तन ने विभिन्न कारणों का उल्लेख करते हुए कोई प्रतिसाद नहीं दिया था।

2.3. केपीटी की गांधीधाम टाउनशिप भूमि के लिए दर ढांचे की वैधता में विस्तार किए जाने के प्रत्येक अवसर पर, जैसाकि 2010 के भूमि नीति दिशानिर्देशों और 2014 के संशोधित भूमि नीति दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट किया गया है, इस प्राधिकरण ने गांधीधाम टाउनशिप भूमि के लिए दर ढांचे की वैधता का समय-समय पर विस्तार इस

प्राधिकरण द्वारा संशोधित किए जाने तक 2 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ किया था। विस्तार आदेशों में विनिर्दिष्ट किया गया है कि 2 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ मौजूदा पट्टा किरायों का विस्तार मौजूदा परिदृश्य में अन्तर से बचने के लिए केवल एक अस्थायी व्यवस्था है। विस्तार आदेशों में भी यह कहा गया है कि केपीटी द्वारा दाखिल किए जाने वाले प्रस्ताव के आधार पर गांधीधाम टाउनशिप के लिए निर्धारित किए जाने वाले पट्टा किरायों को पूर्वव्यापी प्रभाव दिया जाएगा, जैसाकि केपीटी द्वारा अनुरोध किया गया है।

2.4. केपीटी के अनुरोध पर केपीटी की गांधीधाम टाउनशिप भूमि हेतु मौजूदा दर ढांचे में विस्तार करते समय इस प्राधिकरण ने अपने आदेश सं. टीएमपी/20/2010—केपीटी दिनांक 15 जनवरी 2016 द्वारा भी केपीटी को निदेश दिया था कि केपीटी की गांधीधाम टाउनशिप भूमि के लिए दर ढांचे हेतु अपना प्रस्ताव 15 फरवरी 2016 तक दाखिल करे।

2.5. इस प्राधिकरण द्वारा आदेश सं. टीएमपी/20/2010—केपीटी दिनांक 24 मई 2017 द्वारा स्वीकृत केपीटी की गांधीधाम टाउनशिप भूमि के मौजूदा दर ढांचे का पिछला विस्तार 30 सितम्बर 2017 तक है।

3.1. केपीटी ने अपने पत्र दिनांक 11 अप्रैल 2016 द्वारा 01 जनवरी 2014 से 5 वर्षों की अवधि के लिए केपीटी की गांधीधाम टाउनशिप भूमि के दर ढांचे के संशोधन के लिए अपना प्रस्ताव जमा किया था। केपीटी का प्रस्ताव “प्रशुल्क मामला” रूप में पंजीकृत किया गया था और उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठनों से परामर्श किया गया था।

3.2. केपीटी के प्रस्ताव पर एक संयुक्त सुनवाई 30 जुलाई 2016 को केपीटी परिसर में आयोजित की गई थी। संयुक्त सुनवाई में यथा सहमति अनुसार, केपीटी से संयुक्त सुनवाई से निकलकर आने वाली कुछ बातों पर कार्रवाई करने के लिए हमारे पत्र दिनांक 23 अगस्त 2016 द्वारा अनुरोध किया गया था। केपीटी ने अपने पत्र दिनांक 02 दिसम्बर 2016 द्वारा हमारे द्वारा मांगी गई अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण और संयुक्त सुनवाई के कार्यवृत्त से निकलकर आए कार्रवाई बिन्दु पर प्रतिसाद भेजा था।

3.3. प्रस्ताव की प्राथमिक संवेद्धा पर, केपीटी से हमारे पत्र दिनांक 02 अगस्त 2016 द्वारा अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण भेजने का अनुरोध किया गया था।

4.1. यहां पर उल्लेख करना प्रासंगिक है कि भूमि नीति दिशानिर्देश, 2014 के पैरा 10 में इविड दिशानिर्देशों का दायरा विनिर्दिष्ट किया गया है। उक्त पैरा में यह भी कहा गया है कि उक्त दिशानिर्देश कांडला, मुख्बई और कोलकाता पत्तनों के टाउनशिप क्षेत्रों से संबंधित भूमियों पर लागू नहीं हैं जिनके लिए अलग नीति बनाई जाएगी। संशोधित भूमि नीति दिशानिर्देश, 2014 के पैरा 5 में जनवरी, 2014 में एमओएस द्वारा जारी किए गए पूर्व दिशानिर्देशों के पैरा 1. में यथा विनिर्दिष्ट दिशानिर्देशों को लागू किए जाने की गुंजाइश रखी गई है।

4.2. अतः, हमारे पत्र सं. टीएमपी/8/2014—सामान्य दिनांक 09 फरवरी 2016 द्वारा एमओएस से यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था कि किन भूमि नीति दिशानिर्देशों के अधीन केपीटी के गांधीधाम टाउनशिप क्षेत्र का पट्टा किराया शासित किया जाए जब तक इन तीन महापत्तन न्यासों में टाउनशिप क्षेत्रों के लिए एमओएस द्वारा अलग नीति तैयार नहीं की जाती है। चूंकि एमओएस से स्पष्टीकरण की प्राप्ति की प्रतीक्षा थी, इसलिए हमारे पत्र दिनांक 22 अप्रैल, 2016 और अनुवर्ती पत्रों दिनांक 28 जून 2016 और 14 जुलाई 2016 द्वारा एमओएस को दोबारा स्मरण करवाया गया था। इस बारे में एमओएस से नियमित रूप से पत्राचार हो रहा था। केपीटी से भी हमारे पत्र दिनांक 16 मई 2016 द्वारा अनुरोध किया गया था कि इस मामले में एमओएस से बातचीत की जाए।

5. तत्पश्चात, केपीटी ने अपने पत्र दिनांक 07 जुलाई 2016 में कहा था कि पत्तन ने टाउनशिप के लिए मसौदा भूमि नीति दिशानिर्देश, 2015 तैयार कर लिया है और केंद्रीय सरकार के अनुमोदन के लिए अपने बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात एमओएस को अप्रेषित कर दिया है।

6. एमओएस को भेजे गए हमारे पत्रों के प्रतिसाद में, एमओएस ने सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अपने पत्र दिनांक 02 अगस्त 2016 द्वारा सूचित किया है कि गांधीधाम टाउनशिप से संबंधित भूमि पर केंद्रीय मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। एमओएस ने यह भी सूचित किया है कि केपीटी के गांधीधाम टाउनशिप के दर ढांचे के संशोधन के लिए प्रस्ताव को रोककर रखा जाए और इस संबंध में एमओएस द्वारा नीति के बारे में बताए जाने के बाद ही कार्यवाही की जाए।

7. उपर्युक्त अनुच्छेदों से यह देखा जा सकता है कि यह मामला अप्रैल 2016 से निपटान के लिए लंबित है। केपीटी में गांधीधाम टाउनशिप भूमि पर भूमि नीति एमओएस से अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। चूंकि केपीटी का प्रस्ताव “प्रशुल्क मामला” के रूप में पंजीकृत किया गया था, इसलिए इस मामले को अनिश्चितकाल तक लंबित रखना इस प्राधिकरण के लिए उपर्युक्त नहीं होगा।

8. उपर्युक्त स्थिति के मददेनजर और यह भी स्वीकार करते हुए कि इस मामले को अनिश्चितकाल तक खुला नहीं रखा जा सकता, इसलिए इस प्राधिकरण ने समग्र विचार-विमर्श के आधार पर प्रस्ताव दिनांक 11 अप्रैल 2016 को बन्द करने का निर्णय लिया है। एमओएस द्वारा संप्रेषित की जाने वाली नई नीति के आधार पर केपीटी से जैसे और जब संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हो उसे नया मामला माना जाएगा।

टी. एस. बालासुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./185/17]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS**NOTIFICATION**

Mumbai, the 27th July, 2017

No.TAMP/25/2016-KPT.—In exercise of the powers conferred under Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), this Authority hereby disposes of the proposal received from the Kandla Port Trust (KPT) for revision of rate structure of Gandhidham Township of KPT, as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

No. TAMP/25/2016-KPT

Kandla Port Trust (KPT)

- - -

Applicant

QUORUM:

- (i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii). Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 21st day of July 2017)

This case relates to the proposal dated 11 April 2016 received from the Kandla Port Trust (KPT) for revision of rate structure of Gandhidham Township of KPT.

2.1. This Authority *vide* Order No.TAMP/20/2010-KPT dated 9 April 2012 had approved lease rental for KPT Gandhidham Township. The Order was notified in the Gazette of India *vide* Notification no.119 dated 4 May 2012. The lease rentals revised by this Authority were implementable with retrospective effect from 01 January 2009 and valid for a period of five years, i.e. upto 31 December 2013.

2.2. Thereafter, this Authority has, based on the request made by the KPT, extended the validity of the existing rate structure for Gandhidham Township Land of KPT from time to time *vide* its Orders dated 30 June 2014, 31 December 2014, 30 June 2015. While on each extension, this Authority has advised the port to file its proposal for revision of rate structure for Gandhidham Township Land. However, the port has not responded stating various reasons.

2.3. On each occasion while extending the validity of the rate structure for Gandhidham Township Land of KPT, as stipulated in the Land Policy Guidelines of 2010 and revised Land Policy Guidelines 2014, this Authority approved the extension of validity of the rate structure for Gandhidham Township land from time to time with 2% annual escalation till they are revised by this Authority. The extension Orders stipulated that the extension of the existing lease rentals with an annual escalation of 2% is only a provisional arrangement to avoid a vacuum in the current scenario. The extension Orders also stated the lease rentals to be fixed for the Gandhidham Township based on a proposal to be filed by the KPT may have to be given retrospective effect, as requested by the KPT.

2.4. While extending the existing rate structure for Gandhidham Township Land of KPT on the request of KPT this Authority *vide* its Order No.TAMP/20/2010-KPT dated 15 January 2016 also directed KPT to file its proposal for revision of rate structure for Gandhidham Township Land of KPT positively by 15 February 2016.

2.5. The last extension of existing rate structure of Gandhidham Township Land of KPT granted by this Authority *vide* Order No.TAMP/20/2010-KPT dated 24 May 2017 is till 30 September 2017.

3.1. The KPT *vide* its letter dated 11 April 2016 has submitted its proposal for revision of rate structure of Gandhidham Township of KPT for the period w.e.f., 01 January 2014 for a period of 5 years. The proposal of KPT was registered as a “tariff case” and taken on consultation with the users/ user organisations.

3.2. A joint hearing on the proposal of KPT was held on 30 July 2016 at the KPT premises. As agreed at the joint hearing, the KPT was requested *vide* our letter dated 23 August 2016 to take action on a few points arising out of joint hearing. The KPT *vide* its letter dated 02 December 2016 has furnished its response to additional information/ clarification sought by us and the action point flowing from the proceedings of the joint hearing.

3.3. On preliminary scrutiny of the proposal the KPT was requested to furnish additional information/ clarifications *vide* our letter dated 02 August 2016.

4.1. It is relevant here to state that Para 10 of the Land Policy Guidelines, 2014 stipulates the scope of the ibid Guidelines. The said para states that the said guidelines are not applicable to the lands relating to Township areas of Kandla, Mumbai and Kolkata Ports for which separate policy will be formulated. Para 5 of the amended Land Policy Guidelines 2014 maintains the scope of applicability of the guidelines as stipulated in the para 10 of the earlier guidelines issued by the MOS in January 2014.

4.2. The MOS was, therefore, vide our letter No.TAMP/8/2014-Genl. dated 09 February 2016 requested to clarify under which Land Policy Guidelines the lease rent of Gandhidham Township area of KPT is governed till separate policy is formulated by the MOS for the township areas in these three Major Port Trusts. Since clarification from the MOS was still awaited, the MOS was again reminded vide our letter dated 22 April 2016 and subsequent letters dated 28 June 2016 and 14 July 2016. This was followed by regularly with MOS. The KPT was also requested to pursue the matter with MOS vide our dated 16 May 2016.

5. Subsequently, the KPT in its letter dated 07 July 2016 has stated that the port has formulated draft Land Policy Guidelines 2015 for Township and forwarded to MOS after approval of its Board for approval of the Central Government.

6. In response to our letters to MOS, the MOS vide its letter dated 02 August 2016 has informed with the approval of Competent Authority that a proposal seeking approval of the Union Cabinet on Land relating to Gandhidham Township is being prepared. The MOS has also informed that the proposal for revision of rate structure of Gandhidham Township of KPT may be kept on hold and taken up after the MOS conveys the policy in this regard.

7. It can be seen from the above paragraphs that the case is pending for disposal since April 2016. Land Policy on Gandhidham Township Land at KPT is not yet received from MOS. Since the proposal of KPT is registered as a “tariff case” it may not be appropriate for this Authority to keep the case pending indefinitely.

8. In view of the above position and also recognising that the case cannot be kept open indefinitely, this Authority based on collective application of mind decides to close the proposal dated 11 April 2016 of KPT. The revised proposal as and when received from KPT based on new policy to be communicated by MOS, will be treated afresh.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./185/17]